Thailand and Philippines during the last two years.

(b) The foreign exchange spent on his visit to USSR, Iraq and Mexico was Rs. 16,041/-. The expenditure on visit to Thailand and Philippines was met by United Nations Development Programme and the subsistence allowance paid for these visits by UNDP was $ 436.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिया गया ऋण

1376. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत एक वर्ष के दौरान कमजोर वर्गों के लोगों को कितना ऋण दिया गया और उनको ऋण किस ब्याज दर पर दिया गया ;

(ख) प्रत्येक बैंक ने राज्य-वार कितना ऋण दिया; और

(ग) समाज के दुर्बल वर्गों के लिए बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के अपने कार्यक्रम के अंग के रूप में समाज के कमजोर वर्गों के लोगों जैसे भूमिहीन मजदूरों सीमांकित और छोटे किसानों, देहाती कारीगरों और शिल्पियों को ऋण प्रदान करते हैं । परन्तु, इस ऋणकर्त्ता समूह के सबसे कमजोर वर्ग के लिए वे विभेदी ब्याज दर योजना चला रहे हैं जिसके अंतर्गत पात्र ऋणकर्त्ताओं को विनिर्दिष्ट सीमाओं के अंदर 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है । इस योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों के बारे में उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	जून, 1978	जून, 1979
बकाया रकम (करोड़ रुपयों में)	73.82	113.73
ऋणकर्त्ता खातों की संख्या	14,72,964	18,33,305

(ख) सूचना विवरण में दी गयी है जो सभा पटल पर रखा गया है [संचालय में रखा गया) है । देखिए संख्या Lt-617/80]

(ग) समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे विभेदी ब्याज दर योजना को जोरदार तरीके से कार्यान्वित करें । सरकार ने पात्र कारीगरों, शिल्पियों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को 65,000 रुपये तक के ऋण देने के लिए भी बैंकों को अनुमति दी है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 33.3 प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये जाने के लिए निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है । बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए बढ़ायी गयी ऋण राशि का एक महत्वपूर्ण भाग 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को दिया जाए । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने के कार्यक्रम की गति भी तेज की जाएगी ।

वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों का ब्योरा

1377. **श्री राम लाल राही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध विभिन्न संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न वर्गों के पदों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों के निर्धारित कोटे को न भरने का एक मात्र कारण इनके प्रति उदासीन रवैया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरक्षित पदों के निर्धारित कोटे को भरने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोई नई नीति सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो आरक्षण संबंधी नीति के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Export of Essential Commodities

1378. **SHRI SOMNATH CHATTERJEE:** Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state whether Government are proposing to export even essential commodities?